(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1996 के "दि इकनोमिक्स टाइम्स" में "हायर वैरीएशन इन डब्ल्यू पी॰ आई॰ ऑफ बेसिक फूड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में आम आदमी के प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे गेहूं, चना, नारियल का तेल, आलू और आटा की कीमतों में दिसम्बर, 1993-94, दिसम्बर, 1994-95 और दिसम्बर, 1995-96 में निरन्तर वृद्धि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए दिसम्बर के अंत तक विनिर्दिष्ट खाद्य मदों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू॰पी॰ आई॰) द्वारा मापित मूल्य वृद्धि की मात्रा नीचे सूचीबद्ध है:-

थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि

(दिसम्बर अंत के अनुसार)

मदें	प्रतिशत वृद्धि			
	1993	1994	1995	1996
गेहूं	13.1	9.7	-1.6	31.3
चना	74.7	-10.3	-38.3	47.3
नारियल का तेल	-26.7	12.1	0.3	46.8
आलू	58.2	-15.3	7.4	80.9
आटा	5.8	6.4	3.5	43.3

उक्त पांच वस्तुओं, जिन्होंने दिसम्बर, 1996 में उच्च वार्षिक मूल्य वृद्धि दर्ज की है, की तुलना में अन्य प्राथमिक वस्तुओं ने या तो गिरावट दर्ज की है या उनमें काफी कम वृद्धि हुई है जैसे चावल (13 प्रतिशत), अरहर (-1.3 प्रतिशत), प्याज (-21.5 प्रतिशत), चाय (-4.3 प्रतिशत), सरसों का तेल (-7.9 प्रतिशत), मूंगफली का तेल (-3.4 प्रतिशत), वनस्पति (-2.6 प्रतिशत), बाजरा (3.9 प्रतिशत), उड़द (11.5 प्रतिशत), दूध (2.9 प्रतिशत) और चीनी (1.2 प्रतिशत)।

करेंसी नोटों की कमी के संबंध में प्रकाशित समाचार

1064. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "प्रीमियम ओन करेंसी मेटल्स गेनिंग करेंसी इन सिटी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में छोटी कागजी करेंसी की उपलब्धता में भारी कमी होने के कारण छोटी करेंसी के नए नोट काले बाजार में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जून, 1996 से लेकर अब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक महीने में 1,2 और 5 रुपए के नए करेंसी नोट औसतन कुल कितने मूल्य के जारी किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को निम्न मूल्यवर्ग के नए नोटों के लिए अदा किए जा रहे किसी प्रीमियम के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी नीति के अनुसार, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण कर दिया गया है। तदनुसार, नोट प्रिंटिंग प्रेसों ने क्रमश: सितम्बर, 1994, जनवरी 1995 और नवम्बर, 1995 से इन मूल्यवर्गों के नोटों की छपाई बंद कर दी है।

Directive Regarding Reservation to SC/ ST Employees in Punjab and Sind Bank

1065. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether some directives have been issued to the management of Punjab and Sind Bank to provide reservation for SC/ST employees against promotion given to 48 officers from JMGS-I to MMGS-II in 1994 under normal channel of promotion policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the provisions of said directives have since been implemented; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) It is reported by the Punjab & Sind Bank, that High Court of Punjab & Haryana, in a Judgement dated 22.12.95 issued direction to the Bank to provide reservations for SC/ST employees as

per existing rules against promotion given to 48 officers from JMGS-I to MMGS-II in the year 1994. In compliance with the orders the bank conducted a special test for SC/ST candidates and promoted 10 SCs and one ST candidates who qualified for promotion. With this a backlog of 3 vacancies of STs has been created which has been carried forward.

Investment of Black Money in Real Estate

1066. SHRI JANARDHANA POOJARI:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that most of the black money is invested in real estate in the country,

(b) whether Government are aware that during last one year prices of real estate have risen very high;

(c) if so, what steps Government have taken/ propose to take to control the role of black money in real estate prices in view of Government policy of providing houses to weaker sections and salaried class; and

(d) the amount of income tax realised from property dealers in the country during the last three years and during the current year so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Real estate is one of the various modes for investment of unaccounted money in the country.

(b) There is no authentic information available in this regard.

(c) There are specific provisions under the Income-tax Act to control the role of black money in real estate prices. These are inter alia:

(i) Provisions of Chapter XX-C under which Central Govt. has been empowered with a pre-emptive right to purchase immovable properties,

(ii) Provisions relating to search and seizure operations u/s 132,

(iii) Provisions relating to survey operations u/s 133A,

(iv) Provisions relating to verification of information u/s 133 (6),

(v) The benefit of indexation provided in case of long term capital gains,

(vi) Rate of tax on long term capital gains at 20%, which is less than the maximum marginal rate of Income-tax,

(vii) In depth investigations in cases selected for scrutiny,

(d) No separate data is maintained in this regard.

अवसंरचना हेतु काले धन का उपयोग

1067. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पी॰एम॰ पान्ट्स ब्लैकमनी इन्वैस्टेड इन इन्फ्रास्ट्रक्चर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में काले धन का उपयोग करने से संबंधित कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो देश में वर्तमान में काले धन की मात्रा के संबंध में सरकार के क्या अनुमान हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) संसद में दिनांक 28 फरवरी, 1997 को पुर:स्थापित किए गए वित्त, विधेयक में प्रस्ताव किए गए हैं, जिनमें एक नई स्वैच्छिक प्रकटन योजना भी शामिल है।

(ग) चूंकि हाल ही में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए देश में इस समय काले धन की मात्रा के अनुमान बता पाना संभव नहीं है।

Loans Provided by Nationalised Banks for Development of Agriculture

1068. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) The State-wise loans, which have been provided by the nationalised banks in the